

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर

प्रधानमंत्री जी का भाषण

मेरे प्यारे देशवासियो, भाइयो, बहनो और प्यारे बच्चो,

आज फिर वही खुशी का दिन आया है, जब हम मिलकर अपनी आज़ादी का त्यौहार मना रहे हैं। आप सबको मैं इस शुभ मौके पर बधाई देता हूँ।

अट्ठावन साल पहले यह तिरंगा पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसी ऐतिहासिक मुकाम से पहली दफ़ा फहराया था और इस तरह करोड़ों भारतवासियों का आजादी पाने का सदियों पुराना सपना साकार हो गया।

अगले साल हम पहली जंग-ए-आजादी की एक सौ पचासवीं सालगिरह मनाना शुरू करेंगे। इसके जरिए हम उस जंग के उन वीर सेनानियों को फिर से याद कर सकेंगे जिन्होंने हमारी आजादी की संग-ए-बुनियाद डाली थी। सन् अठारह सौ सत्तावन में इसी लालकिले से बहादुरशाह ज़फ़र ने आजादी की लड़ाई का ऐलान किया था। झांसी

की रानी लक्ष्मी बाई, पेशवा नाना साहेब, तांत्या टोपे और लखनऊ की बेगम हज़रत महल उन सबका नारा था - **"दिल्ली चलो।"** इस नारे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फिर से बुलंद किया और 1947 में वह मकसद पूरा हो गया। आज हमें उनकी कुर्बानियों को याद करना है। आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम उनके जोश और आत्मविश्वास से काफी कुछ सीख सकते हैं।

यह दिन आजादी पाने की विजय पर गर्व करने और खुशी मनाने का दिन है। एक ऐसा खुशी का दिन जिसमें हर भारतवासी चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, शरीक होता है। एक ऐसा दिन जब हम अपने वीर जवानों **और** सुरक्षा बलों को धन्यवाद देते हैं, उनकी बहादुरी को नमन करते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा **तैयार** रहेंगे।

गांधी जी ने भी डांडी मार्च के जरिए पचहत्तर साल पहले आजादी का यही सपना देखा था। उस आंदोलन से उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। हमें आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के त्याग और बलिदान तथा उनकी

कल्पना को याद करना होगा और यह विचार करना होगा कि हम उनकी कल्पना को साकार करने में कितने कामयाब रहे हैं।

गांधी जी की कल्पना क्या थी? उन्होंने कहा था, "मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमियों को यह अनुभव हो कि देश उनका है और इसके निर्माण में उनकी कारगर भूमिका है। एक ऐसा भारत जिसमें सभी लोगों का न कोई ऊंचा वर्ग होगा और न निचला। एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय मैत्री भाव के साथ रहेंगे। महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे।" उन्होंने यह भी कहा था, "मेरे सपनों का स्वराज गरीबों का स्वराज है। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जब तक गरीबों को सामान्य सुख-सुविधाओं की गारंटी नहीं मिलती तब तक स्वराज पूर्ण स्वराज नहीं माना जा सकता।" क्या हम इस कल्पना के नजदीक पहुंच पाए हैं?

भाइयो और बहनो,

गत वर्ष में हमारा प्रयास यही रहा है कि हम गांधी जी की कल्पना के भारत का निर्माण करें। हमारी सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का भी यही मकसद है। पिछले साल मैंने इसी दिन लाल

किले से यह कहा था कि मुझे कोई वायदे नहीं करने हैं, बल्कि वायदे निभाने हैं। वायदे पूरे करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और देश की तरक्की के लिए अनेक अहम फैसले लिए। ये फैसले लेते समय हमारी नज़र हमेशा आम आदमी पर रही है। हमारी सरकार की यही कोशिश रही है कि हमारा देश दिनोंदिन प्रगति के रास्ते पर बढ़ता जाए और विकास के लाभ समाज के हर तबके को समान रूप से मिलें। हमारा लक्ष्य सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि ऐसा विकास जिससे आम आदमी के जीवन में सुधार हो।

आज हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की हो रही है। गत वर्ष हमारे आर्थिक विकास की दर 7 फीसदी रही है और इस वर्ष भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। हमारे इतिहास में इस तरह की तरक्की कभी नहीं देखी गई। मुझे विश्वास है कि यदि हम इस गति को बनाए रखेंगे तो आने वाले 5-10 सालों में पूरे भारत से गरीबी, भुखमरी, जिहालत और बीमारियों को मिटा सकेंगे। यह लक्ष्य कोई सपना नहीं बल्कि इसे हासिल करना **मुमकिन** है।

यह केवल हम ही नहीं बल्कि सारी दुनिया मान रही है कि भारत आधुनिक जमाने के अक्वलीन देशों में से एक है। विश्व के देश हमारी ओर हैरतभरी निगाहों से देख रहे हैं कि भारत किस तरह आर्थिक मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। यह आर्थिक विकास एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत हो रहा है। हमारा देश एक बहु-सांस्कृतिक, बहु-जातीय, बहु-धर्मी और बहु-भाषी देश है।

दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहाँ इस तरह की 100 करोड़ की आबादी वाला देश अपनी सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति लोकतंत्र के माध्यम से कर रहा हो। इसी वजह से सारी दुनिया की निगाहें हम पर टिकी हैं। यह हम सभी की मेहनत का फल है कि आज हमने विश्व मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है और हम अक्वलीन देशों की कतार में खड़े होकर फ़ख़ महसूस कर रहे हैं।

भाइयो और बहनो,

मेरा मानना है कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है और वह भविष्य सम्भव है। इसके लिए हमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर

ध्यान देना होगा। हमें इन्हीं दोनों कदमों पर आगे बढ़ना होगा ताकि विकास के लाभ समाज के हर तबके तक पहुंच सकें।

पिछले साल इसी दिन राष्ट्र को संबोधित करते हुए मैंने विकास को बढ़ावा देने के लिए 7 सूत्रों का जिक्र किया था। ये सूत्र थे - कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शहरी विकास तथा **Infrastructure**. आज हम इसका जायजा लेंगे कि इन सात सूत्रों में क्या प्रगति रही।

हमारी तवज्जो खास तौर से खेती पर रही है। किसान हमारे देश के विकास की रीढ़ हैं। वे अपनी कड़ी मेहनत से देश के लिए अनाज पैदा करते हैं। आज उन्हीं की वजह से हमारे देश में अन्न की कमी नहीं है। पूरा देश उनका आभारी है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जिस आर्थिक विकास का मैंने जिक्र किया उसके फायदे समाज के हर **नागरिक** तक अभी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए हैं। खास तौर से यह हमारे ग्रामीण इलाकों में देखा गया है। खेती में उस रफ्तार से विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। आर्थिक विकास में हिस्सेदार बनना हर किसान का हक है और आज भी देश के साथ फीसदी से ज्यादा

लोग खेती पर निर्भर हैं। इसलिए हमने ग्रामीण भारत के लिए एक नये दौर की शुरुआत की है। हमने किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनमें किसानों को आसानी से कर्ज दिलाना, निवेश और गोदामों की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना, सब्जी-फल की पैदावार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत करना, कृषि में रिसर्च और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना शामिल है। हमारा उद्देश्य है कि सन् 2007 तक हरेक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र हो। इस तरह रिसर्च और ट्रेनिंग की सहूलियतें हर ग्रामवासी के नजदीक आ **जाएंगी**। देश में खुश्क भूमि और बारिश पर निर्भर रहने वाले इलाकों में किसानों की दिक्कतों को दूर करने की तरफ भी हम पूरा-पूरा ध्यान देंगे। हम इसके लिए एक **National Rainfed Area Authority** का गठन करने पर विचार कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि आने वाले सालों में कृषि की उन्नति तेजी से हो और हम एक नयी हरित क्रांति लाएं। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

भाइयो और बहनो,

लेकिन बुनियादी ढांचे के बगैर भारत के ग्रामीण इलाके विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने "भारत निर्माण" की योजना बनाई है। "भारत निर्माण" के तहत एक करोड़ हेक्टेयर खुशक जमीन की सिंचाई होगी। ऐसे सभी गांव जिनकी आबादी 1000 से ज्यादा हो और पहाड़ी इलाकों में 500 से ज्यादा हो, सड़कों से जोड़ दिए जाएंगे। सवा दो करोड़ घरों में बिजली की सप्लाई की जाएगी और इस तरह देश के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध हो जाएगी। गांवों में 60 लाख मकान बनाए जाएंगे। बची हुई 74,000 ग्रामीण बस्तियों को पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। हर गांव में कम से कम एक टेलीफोन अवश्य होगा। मुझे पूरा यकीन है कि "भारत निर्माण" से हमारे ग्रामीण इलाके तेजी से विकसित होंगे।

हमारी विकास योजनाओं की यह नीति है कि इनमें आम आदमी खास तौर से ग्रामवासी भागीदार बने और वह इन योजनाओं को अपनी ही योजना समझे। आम आदमी को विकास योजनाओं में हिस्सेदार

बनाने के लिए हमारे पास तरीका मौजूद है और वह है - पंचायतें। श्री राजीव गांधी जी ने भी इस "पंचायती राज" का सपना देखा था। आज जिला, ताल्लुका और ग्रामीण स्तर पर पंचायतों को इसमें अपना फर्ज अदा करना होगा। हमारे संविधान में पंचायतों को सिर्फ आर्थिक विकास की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की भी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायती राज को सबसे अहम जिम्मेदारी निभाने का यह मौका "भारत निर्माण" के जरिये दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि पंचायतों के माध्यम से "भारत निर्माण" एक ठोस कार्यक्रम बन सकेगा।

मेरे प्यारे देशवासियो,

हम न सिर्फ गांवों की ओर तवज्जो दे रहे हैं बल्कि अपने शहरों की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दे रहे हैं। इस समय देश की एक तिहाई आबादी शहरों में बसती है और जिस रफ्तार से देश का शहरीकरण हो रहा है, वह वक्त दूर नहीं जब भारत की 50 फीसदी आबादी शहरों में होगी। भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद हजारों साल पहले सिंधु नदी पर बसे हमारे शहरों से पड़ी थी। हमने

दुनिया को शहरी आयोजना का पाठ सिखाया लेकिन आज हमारे शहरों की सहूलियतें अक्सर आम आदमी की जरूरतों के मुताबिक कम पड़ती नजर आ रही हैं। शहरों में निवेश लगाकर उन्हें विकास का केंद्र बनाने के लिए "राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन" शुरू किया गया है।

प्यारे देशवासियो,

हमारी आबादी में नौजवानों की तादाद अधिक है। हमने तय किया है कि हम उन्हें अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें मुहैया करके उनके हाथ मजबूत करेंगे। इससे हमारी आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी।

विकास का पूरा फायदा उठाने के लिए यह जरूरी है कि समाज का हर तबका पढ़ा-लिखा हो। सर्व-शिक्षा अभियान को मजबूत बनाकर हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें लड़कियों की पढ़ाई पर खास तवज्जो दी जा रही है। हमें शिक्षा को बच्चों के लिए रोचक, दिलचस्प और उपयोगी बनाने की कोशिश करनी होगी जिससे बच्चों में स्कूल जाने का शौक पैदा हो। हमें खासकर अनपढ़ माँ-बाप के बच्चों की पढ़ाई पर गौर करना होगा। हमारा संकल्प है कि देश का हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित न

रहे। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में महिलाएं पुरुषों के बराबर पढ़ी-लिखी होंगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी। विकलांग बच्चों को सामान्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।

प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ हमें उच्च शिक्षा पर भी तव्वजो देनी होगी। भारत को दुनिया में एक उभरती हुई ज्ञान-शक्ति के रूप में देखा जाता है तो इसकी वजह हमारी **Universities** और **Research** संस्थाएं हैं। यदि हमें प्रगति के रास्ते पर और तेज़ी से बढ़ना है तो इन संस्थाओं को बेहतरीन बनाना होगा और कई नई संस्थाएं शुरू करनी होंगी। मुम्बई, कोलकाता और चेन्नै के विश्वविद्यालयों की इस एक सौ पचासवीं सालगिरह पर हम ऐसा संकल्प लें।

हरेक इंसान को चाहे वह कितना भी शिक्षित क्यों न हो, खुशहाल जीवन बसर करने के लिए सेहतमंद होना जरूरी है। "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" के जरिए चिकित्सा की अच्छी से अच्छी सहूलियतें हर गांव तक पहुंचाई जाएंगी। हमें पूरा यकीन है कि हम देश के हर कोने में अच्छी चिकित्सा सेवाएं मुहैया करके महिलाओं

और बच्चों की सेहत में सुधार ला पाएंगे। इसके नतीजे में हमारी आबादी की बढ़ोतरी में भी अपने-आप कमी आ जाएगी।

गत पचास वर्षों में हम ऐसी कई बीमारियों को भारत से मिटाने में काफी कामयाब रहे हैं जिनसे लोग पुष्ट-दर-पुष्ट पीड़ित रहते थे। मिसाल के तौर पर, कोढ़ की बीमारी 25 राज्यों में दूर कर दी गयी है। पोलियो और टी.बी. पर भी धीरे-धीरे काबू पाया जा रहा है। एड्स की बीमारी अभी हमारे लिए भयंकर परेशानी है। हम इसे रोकने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे और एड्स की रोकथाम को एक जन-आन्दोलन बनाएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर बीमारी की दवाइयां जनता को आम दामों पर मिल सकें।

जैसा कि मैंने पहले कहा था, विकास का असली इम्तिहान यह है कि इससे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कितने परिवार खुशहाल हो रहे हैं। जब तक देश में बेरोजगारी और बेकारी मौजूद है तब तक हम नहीं कह सकेंगे कि हम पूरी तरह से आजाद हैं। इसी मकसद से इन्दिरा जी ने "गरीबी हटाओ" का नारा दिया था। **आज हम कहते हैं कि यदि गरीबी हटानी है तो "रोजगार बढ़ाओ।"** ग्रामीण

इलाकों से बेरोजगारी मिटाने के लिए लोगों को रोजगार की गारंटी देना जरूरी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक को इसी मकसद से तैयार किया गया है। इस महत्वपूर्ण कानून से ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त बदलाव होने की उम्मीद है। इसके साथ-साथ खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन में भी तब्दीली लाई जा रही है ताकि छोटे उद्योग-धंधों से अधिक रोजगार हासिल हो सकें।

भाइयो और बहनो,

विकास की रफ्तार धीमी न हो जाए इसके लिए यह जरूरी है कि बुनियादी ढांचा मजबूत हो। मजबूत **Infrastructure** पर ही विकास निर्भर करता है। बुनियादी ढांचे में रेल, सड़क और बिजली सबसे **खास** हैं। रेल यातायात में बेहतरी लाने के लिए एक योजना बनाई गयी है ताकि भारतीय रेल दुनिया की बेहतरीन रेलों में से एक हो। 25 हजार करोड़ रूपए की लागत से दिल्ली-कोलकाता और दिल्ली-मुंबई के बीच विशेष मालगाड़ी रास्ता बनाने की योजना भी है।

सड़कों के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। 30 हजार किलोमीटर के **Highways** पर निर्माण का नया काम शुरू किया जा

रहा है और जल्दी ही समूचे Golden Quadrilateral को छह लेनों का बनाया जाएगा।

हवाई यातायात में जबरदस्त विकास हुआ है। कई शहरों में बेहतरीन हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। बंदरगाहों के नवीनीकरण और कई नये बंदरगाहों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है।

बिजली की कमी से हमें काफी तकलीफ होती है। बिजली विकास के लिए एक बुनियादी जरूरत है। हमें बिजली के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करके इस कमी को दूर करना होगा। इसके लिए निजी निवेश की भी सख्त जरूरत है। मैंने कई बार कहा है कि सबसे गरीब तबके के लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को मुफ्त में बिजली देने से बिजली इकाइयों की हालत बिगड़ जाती है। हमें तेल की तरह बिजली के लिए भी सही लागत अदा करनी होगी। इसी से बिजली समय पर सही मात्रा में और सही क्वालिटी की मिल सकेगी। इसके अलावा, मेरे अमेरिकी दौरे से परमाणु बिजली के कार्यक्रम में आने वाली रूकावटों में कुछ कमी आयी है और हमें अगले 10 सालों में पानी और कोयले से डेढ

लाख मेगावाट बिजली पैदा करने के अलावा चालीस हजार मेगावाट परमाणु बिजली की पैदावार होने की उम्मीद है।

मेरे प्यारे देशवासियो,

यदि आर्थिक विकास हमारी कल्पना का एक पहलू है तो सामाजिक न्याय एवं आर्थिक समानता इसका दूसरा पहलू। पिछले वर्ष हमारा सबसे बड़ा योगदान यह रहा है कि हम देश को विकास के मार्ग पर वापिस ले आए हैं। समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में आशा की किरण फिर से जगाई है और शांति तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया है।

हमारे देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं की भी खास दिक्कतें हैं। इनमें कई वर्ग सदियों से उपेक्षित रहे हैं। उनको विकास के कामों में पूरा हिस्सेदार बनाना होगा। हम उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देंगे। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। सरकारी नौकरियों में **reservation** पर एक विधेयक लाया गया है। अब हमारी यह कोशिश है कि उन्हें

सरकार के बाहर भी रोजगार और बराबरी का हक मिल सके। आदिवासी भाई कई पुश्तों से जंगल के पास की जमीन पर काश्त करते आए हैं लेकिन इस जमीन पर उनका मालिकाना हक नहीं है जिससे वे गैर-महफूज़ रहते हैं। ये हक 150 साल पहले अंग्रेजी शासन के दौरान उनसे छीन लिए गए थे और इसको दुरुस्त करने के लिए अब हम एक नया कानून ला रहे हैं जिससे जंगल में बसे आदिवासियों को लाभ मिलेगा और जंगलों का बचाव भी हो सकेगा।

हमारे संविधान में सभी पंथों को बराबर का दर्जा दिया गया है और सभी धर्म हमारे गणतंत्र में सुरक्षित हैं। अल्पसंख्यकों को हिफ़ाजत के साथ जिन्दगी गुजारने का पूरा मौका मिलना चाहिए। यही हमारा मकसद है। **इसीलिए** पोटा को समाप्त कर दिया गया है। इससे कई वर्गों के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। अल्पसंख्यकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर एक रिपोर्ट बनाई जा रही है और इसके आधार पर उनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। **अल्पसंख्यकों के लिए** चलाए गए पुराने **15-सूत्री कार्यक्रम** को एक नया रूप देकर फिर से जीवित किया जाएगा। इस नए **15-सूत्री कार्यक्रम** के निश्चित लक्ष्य

होंगे जिन्हें एक सीमित अवधि में हासिल करने की कोशिश की जाएगी।

कारीगरों और बुनकरों, जिनमें अल्पसंख्यक भी काफी हैं, के विकास के लिए एक विशेष योजना चलाई जायेगी जिससे उन्हें आमदनी बढ़ाने में और हुनर को निखारने में मदद मिल सके।

औद्योगिक उन्नति मजदूरों की मेहनत का नतीज़ा है। इस साल मई में हमारी औद्योगिक उन्नति 10 फीसदी से ज्यादा रही है। इसके लिए मैं अपने मजदूर भाइयों को मुबारकवाद देता हूँ। सरकार मजदूर भाइयों की, खासकर गैर-रस्मी क्षेत्र के कामगारों की समस्याओं की ओर पूरा ध्यान देगी। हमारी कोशिश होगी कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो जिससे वे अपने भविष्य के बारे में फिक्रमंद न रहें। लेकिन सभी मजदूरों का भी फर्ज़ है कि वे जिस उद्योग या कारखाने में काम कर रहे हैं, वहां की मैनेजमेंट के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाकर मेहनत से काम करें ताकि उद्योग का मुनाफा बढ़े और इससे उनका भी भला हो।

महिलाएं केवल परिवार की ही नहीं बल्कि देश की रीढ़ होती हैं। इनके हाथ मजबूत करने होंगे। उन्हें ज्यादा अधिकार देने होंगे। हम

महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को रोकने और उन्हें जमीन-जायदाद में हक दिलाने के लिए कानून लाए हैं। संसद और विधानसभाओं में उनके लिए आरक्षण भी दिलाएंगे।

नौजवानों को अपनी सेहत और हुनर की नुमाइश का मौका देने के लिए हम प्रयास करेंगे कि एशियाई खेल **उन्नीस सौ बयासी** के बाद एक बार फिर भारत में हों।

प्यारे देशवासियो,

विकास के इस नये दौर में हमें पूरा ख्याल है कि देश के हर हिस्से में विकास एक ही रफ्तार से हो। देश का कोई हिस्सा विकास की दौड़ में पीछे रह जाए, यह हमारे लिए गवारा नहीं है। सरकार द्वारा हर योजना में पिछड़े इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देश के सरहदी इलाकों के विकास की ओर भी पूरा ध्यान दिया जायेगा। इन इलाकों के लोगों की सड़कों, बिजली, टेलीफोन जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जायेगा।

हमारी नदियां देश की जीवन रेखाएं हैं। ये हमारी महान सभ्यता की बुनियाद हैं। आज हर तरफ से पानी की मांग बढ़ रही है। **21वीं**

सदी में जल सबसे कीमती वस्तु होगी और हर तरफ इसकी कमी महसूस होगी। पानी की बचत के लिए और इसका समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए एक जन-आंदोलन शुरू करना होगा। यह हमारा फ़र्ज है। यह भी जरूरी है कि देश के सभी राज्य आपस में मिलकर एक दूसरे की जरूरतों को पहचानते हुए आपसी झगड़ों को दोस्ताना तरीके से निपटाएं।

हमें अपने पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना होगा। देश में सफाई का एक अभियान चलाना होगा जिससे हमारे शहर, गांव, सड़कें, गलियां और घर साफ-सुथरे रहें। गांधी जी अपने आश्रम में इसी पर जोर देते थे। हमें अपनी नदियों में, हवा में, प्रदूषण को रोकना होगा। हमें अपने जंगलों और कुदरती संपदा को बचाना होगा। हम पर्यावरण के रखवाले हैं और हमारी यह जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को हम यह अमानत हिफ़ाज़त से सौंपें।

भाइयो और बहनो,

पिछले दिनों में कुदरती आफ़तों से भारत के कई इलाकों में काफी तबाही मची है और लोगों को बहुत कष्ट पहुंचा है। दिसम्बर में सूनामी, जनवरी में बर्फ, जुलाई में बाढ़। इन आफ़तों से अनेक लोगों

की कीमती जानें चली गई हैं। सारा देश इन दुखी परिवारों के साथ है। मुझे यकीन है कि जिस प्रकार हमने सूनामी की तबाही को झेला, हम बाढ़ की मुसीबत को भी मिलकर झेलेंगे। मुंबई में गत माह बाढ़ से करोड़ों का नुकसान हुआ है और कई जानें गईं। इन कठिन हालात का मुंबई के नागरिकों ने साहस, हिम्मत और मुश्तैदी के साथ सामना करके दुनिया को दिखा दिया कि मुंबई की अपनी एक अलग पहचान है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मुम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में जल्दी से जल्दी सामान्य हालात बनाने के लिए जो भी मदद की जरूरत होगी, उसे हम पूरा करेंगे। ऐसी कुदरती आफ़तों का मुकाबला करने के लिए एक National Disaster Management Authority का गठन किया गया है। इसके द्वारा टेक्नालॉजी की मदद लेते हुए, आने वाली कुदरती आफ़तों का बेहतर ढंग से मुकाबला किया जा सकेगा।

भाइयो और बहनो,

देश में जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे इलाके हैं जहां अभी भी पूरी तरह अमन और शांति नहीं है। यहां के लोग हिंसा, आतंकवाद

और अशांति से पीड़ित हैं। बिगड़े हालात में हमें **फौज की मदद लेनी पड़ती है**। जहाँ भी हमारे सैनिकों को इस्तेमाल में लाया गया, वहाँ उन्होंने बेहतरीन काम किया है। कई फौजियों की जानें गईं। राष्ट्र की सेवा में मारे गये फौजियों के बच्चों को वजीफा देने के लिए हम "प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना " शुरू करेंगे। हर साल **पाँच हजार** बच्चों को वजीफा दिया जायेगा।

मगर कभी-कभी ज्यादातियाँ हो सकती हैं। उनको ध्यान में रखते हुए और इंसानी हुकूक की हिफाज़त के लिए सरकार ने **Armed Forces Special Powers Act** की सख्तियों को दूर करने के मकसद से एक समिति बनायी है। हम उसकी रिपोर्ट पर पूरी तवज्जो देकर ऐसे कदम उठाएंगे कि इस कानून से इंसानी हुकूक का उल्लंघन न हो।

जम्मू-कश्मीर की हमारी नीति से यह राज्य फिर विकास और शांति के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि इंसानियत के नाते उस राज्य के अवाम को अमन-चैन और शांति का रास्ता अपनाने में मदद करें। उग्रवादी कभी भी

कश्मीरियों के हमदर्द नहीं रहे हैं। जब तक वे हमले जारी रखेंगे, हमारी सेना चौकन्ना रहकर मुंहतोड़ जवाब देती रहेगी। इससे आम आदमी को भी कभी-कभी चोट पहुंच सकती है। मैंने पहले भी कहा था और फिर कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई मसला नहीं है जो बातचीत से हल नहीं हो सकता हो। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे। आइए, हम सब मिलकर असल मसलों का हल तलाश करें जिससे जम्मू-कश्मीर के लोग आराम और शांति की जिंदगी जी सकें। अगर हिंसा जारी रहेगी तो इसका जवाब भी सख्ती से दिया जाएगा। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान की सरकार ने उग्रवादियों पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं लेकिन अधूरे इकदामात से सफलता हासिल नहीं होगी। यह जरूरी है कि उग्रवाद का सारा ढांचा जड़ से उखाड़ा जाए।

भाइयो और बहनो,

उग्रवाद के मामले में, विकास और सुरक्षा का एक दूसरे से गहरा सम्बंध है। हमने लोकतांत्रिक नीतियों से ही उग्रवाद का मुकाबला कामयाबी से किया है। लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार को जनता की असली शिकायतों और उग्रवादियों की साजिशों में फ़र्क पहचानना

होगा। आज हमारे देश की सुरक्षा के लिए कई चुनौतियां हैं - जैसे हिंसा, उग्रवाद, साम्प्रदायिक फसाद, महिलाओं पर अत्याचार और दलितों तथा आदिवासियों के साथ ज्यादतियां। हमारे पुलिस बल हिंसा और उग्रवाद का काबिले तारीफ और मुकम्मल सामना कर रहे हैं। उग्रवाद एक ऐसी चुनौती है जिसका एकजुट होकर सामना करना होगा। मगर इन समस्याओं का राजनैतिक हल निकालने की भी जरूरत है। कई बार पिछड़ापन और विकास का अभाव ही उग्रवाद को पैदा करता है। उग्रवाद का सामना करना आसान नहीं है मगर सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सुरक्षा साधनों का इस्तेमाल करके इस पर काबू पाने में हम जरूर कामयाब होंगे।

मेरे प्यारे देशवासियो,

भारत हमेशा से एक अमन पसन्द देश रहा है। इसकी तकदीर पड़ोसी देशों की तकदीर से जुड़ी है। अपने देशवासियों की खुशहाली हमारा लक्ष्य रहा है। इसलिए हमने अपने हमसायों से केवल दोस्ती चाही। हालांकि यह हमेशा मुमकिन नहीं रहा। अब अमन की तलाश में कुछ सफलता मिलने लगी है। दक्षिण-एशिया की बहुत सी समस्याएं

एक जैसी हैं जिनमें **खास** हैं - गरीबी और जिहालत। इन समस्याओं को हम मिलकर दूर कर सकते हैं।

पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। इसका एक नतीजा है - श्रीनगर-मुज़फ़्फ़राबाद राजमार्ग का खोलना जो जम्मू-कश्मीर की जनता की पुरानी मांग थी और जिस पर बसों के चलने का हर तरफ से इस्तिक्बाल हुआ है। अब इस तरह के और रास्ते दूसरे राज्यों से भी खोलने की बात चल रही है।

पाकिस्तान के रास्ते आते हुए ईरान से भारत तक गैस पाइप लाइन **लाने** की बातचीत चल रही है। इसके आने से हमारी एक आर्थिक कमजोरी दूर हो जाएगी।

यह हमारी दिली मंशा है कि हम दक्षिण एशिया के सभी पड़ोसी देशों के साथ मिलकर गरीबी, बेरोजगारी **और बीमारियों** को मिटाने की मुश्किल चुनौती का डटकर मुकाबला करें। साथ मिलकर काम करने से भारत और पाकिस्तान को संपन्न और खुशहाल बनने के कई मौके मिलेंगे। मुझे यकीन है कि हम इस कल्पना को साकार कर सकेंगे।

अफगानिस्तान के साथ भारत के बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं। हमारी मंशा है कि अफगानिस्तान मज़बूत और खुशहाल बने। चंद दिनों के बाद मैं खुद अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ। हम वहां लोकतंत्र को मजबूत करने और आर्थिक विकास के लिए अफ़गानिस्तान की हर-सम्भव मदद करेंगे।

हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश चीन है जिसके साथ हमारे सम्बंध सदियों पुराने हैं और जिससे हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा और अपनाया है। आज व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में हम चीन से संबंध बढ़ाकर दोनों देशों के फायदे के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। अप्रैल में हुए हमारे आपसी समझौते से इसका रास्ता खुल गया है।

मैं श्रीलंका, मॉरीशस, नेपाल, बंगलादेश, भूटान, मालदीव और म्यांमार के लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और दिल से यकीन दिलाता हूँ कि भारत उनके साथ मिलकर विकास, खुशहाली और शांति को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तैयार है।

अमरीका का मेरा दौरा उस देश के साथ दोस्ती बढ़ाने में एक अहम कदम रहा। हमारे आपस में तकनीकी और आर्थिक सम्बन्धों से देश के विकास में बढ़ोतरी आएगी। इसके साथ-साथ हमारे दोनों

लोकतान्त्रिक देश मिलकर दुनिया में लोकतन्त्र को मजबूत कर सकते हैं। रूस हमारा पुराना दोस्त है। उसने हमारी हर मुश्किल में मदद की है। हम रूस के साथ अपने दोस्ताना सम्बन्धों को और गहरा बनायेंगे।

पूर्व के देशों के साथ भी हम बिरादराना सम्बन्ध बनाना चाहते हैं। सिंगापुर से हमारा व्यापार का समझौता इस पहल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। हम भविष्य में ऐसे और भी समझौते करेंगे।

अब मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी कोशिशों की कामयाबी में विदेशों में बसे हमारे **प्रवासी भारतीयों** ने हमारा खूब हाथ बंटया है। वे खुद दूर-दराज देशों में पहुंचकर अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में तो कामयाब हुए **ही** हैं, इसके साथ ही उन्होंने दुनिया में भारत की छवि बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है। अब सारी दुनिया भारत को एक ऐसी ज्ञान शक्ति के रूप में देखती है जिसके लोग मेहनत, **हुनर** और सभ्यता के धनी हैं। देश में भी, हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, **Scholars** पूरी लगन और मेहनत से काम करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरे देश को उन पर नाज़ है।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार चलाने में सबसे बड़ी चुनौती है - विकास योजनाओं को सही ढंग से लागू करना। खर्च का सही नतीजा लोगों को दिखाई देना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और पंचायतों को आपस में मिलकर काम करना होगा ताकि वे जनता की उम्मीदों को पूरा कर सकें। यदि सरकार को नतीजे देखने हैं तो सरकार के कार्य-संचालन में बदलाव लाना होगा। भ्रष्टाचार और मनमानी के लिए न तो हमारे समाज में और न ही हमारी सरकार में कोई जगह है। हम इसको बर्दाश्त करने के लिए **हरगिज** तैयार नहीं। सरकारी कर्मचारियों को सेवा की भावना से काम करने की जरूरत है और इसलिए उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। सरकार को पारदर्शी तथा कारगर बनना होगा। हाल ही में अपनाया हुआ "सूचना का अधिकार" विधेयक इस दिशा में एक ठोस कदम है।

भाइयो और बहनो,

भारत प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा है। **सारी दुनिया** हमारी इज्जत करने लगी है। अब गरीबी, **जिहालत** और बीमारियों पर काबू

पाना मुमकिन हो गया है। यह हम सब की जिंदगी में ही सम्भव है।
हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने यह मुमकिन कर दिया है।

मेरे प्यारे देशवासियो,

देश के इतिहास में कभी-कभी वह वक्त आता है जब कहा जा सकता है कि इतिहास बनाने का वक्त आ गया है। अभी हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जब दुनिया चाहती है कि भारत सफल हो और यह उभरकर दुनिया के मंच पर अपनी जगह हासिल करे। हमारी तरक्की में कोई बाहरी अड़चन नहीं है, अगर कोई अड़चन है तो वह है - देश के अंदर।

हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना होगा। हमें संकल्प लेना होगा कि हम इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने देश को जल्दी से जल्दी संपन्न और खुशहाल बनायें। हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि हम दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। भारतवासी दुनिया के किसी भी दूसरे देश के बाशिंदों के बराबर हैं। हमारे राजनैतिक ढांचे और नेताओं को इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए सूझबूझ, सच्चाई और दूरदर्शिता दिखानी होगी ताकि हम भारत का नाम दुनिया के देशों में बुलन्द कर सकें।

मेरे प्यारे देशवासियो, भाइयो और बहनो,

आइए, हम सब एकजुट होकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी विविधता में एकता को महसूस कर एक नये भारत का निर्माण करें। एक ऐसा भारत जहां सरकार और आम आदमी के बीच दीवारें न हों। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक दुनिया के मंच पर खड़े होकर गर्व से कह सके कि मैं भारतवासी हूँ। आइये, हम सब मिलकर ऐसा भारत बनायें।

प्यारे बच्चों, अब मेरे साथ मिलकर बोलें --

जय हिन्द!

जय हिन्द!

जय हिन्द!

.....